of the University of Delhi in place of Shri Balraj Madhok in terms of the proviso to clause (1) of the said Statute".

MR. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of clause (1) (xvi) of Statute 2 of the Statutes of the University of Delhi, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from among themselves to serve as member of the Court of the University of Delhi in place of Shri Balraj Madhok in terms of the proviso to clause (1) of the said Statute".

The motion was adopted.

12.56½ HRS.

INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Railways Act, 1890.

MR. SPEAKER : Motion moved :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Railways Act, 1890".

12.57 HRS.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का विरोध करने के पहले मेरा एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है। मैंने इस बिल के इंट्रोडक्शन का विरोध करने का प्रस्ताव किया है, लेकन इस पर आने के पहले मैं व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अगर आप नियम 71 (1) देखें तो उसके अनुसार यह है कि :

"Whenever a Bill seeking to replace an Ordinance with or without modification is introduced in tht House, there shall be placed before the House along with the Bill...."—

मैं चाहूंगा कि आप इस को ठीक ढंग से समझ कर अपनी रूलिंग दें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और नियम पर आप की रूलिंग इस सदन को माननी पड़ेगी।

"a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance".

मैं मानता हूं कि आर्डर पेपर पर यह लिखा हुआ है। आइटम नं० 10 अगर आप देखें तो उस में लिखा हुआ है कि:

"The explanatory statement giving reasons for immediate legislation by the Indian Railways (Amendment) Ordinance, 1968, as required under rule 71(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, has been laid on the Table on the 11th November 1968".

रूल 71(1) यह नहीं कहता है कि विधेयक को पेश करने के पहले स्टेटमेंट को सभा पटल पर रखना चाहिए। 71 (1) यह कहता है कि जब बिल पेश होगा तब **एलांग विद दि बिल** यानी बिल के साथ देना होगा कि इस के बारे में आर्डिनेन्स क्यों लाना पड़ा। मुझे इस पर आप की व्यवस्था चाहिये। अगर आप 71 (2) देखेंगे तो जो बहुत बड़ी गलती मंत्री महोदय ने की है तथा इस सरकार ने की है वह आप को मालूम हो जायेगी। 71 (2) यह कहता है कि :

"Whenever an Ordinance, which embodies wholly or partly or with modification the provisions of a Bill pending before the House, is promulgated a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance shall be laid on the Table at the commencement of the session following the promulgation of the Ordinance'.

71 (2) यह कहता है अगर कोई भी विधेयक सदन के सामने पहले से हो जिस को लेकर आर्डिनेन्स प्रोमलगेट करना पड़ा हो राष्ट्रपति को तो जब सदन की

*Published in Gazette of India Extra-ordinary Part II, section 2, dated 15-11-68.

बैठक बुलाई जाएगी तो पहले ही दिन उस सदन के सामने यह कारण बताने वाला बयान सरकार की ओर से आना चाहिए। 71(2) के अन्तर्गत उन लोगों ने अपना बयान यहां पर पेश किया जबकि 71(1) में जो बयान आपका आना चाहिये वह विधेयक के साथ आना चाहिये।

मैं मानता हूं कि एक तांत्रिक प्रश्न मैं उठा रहा हूं। लेकिन नियम तो नियम हैं और उनके मुताबिक चलना भी होगा। अभी-अभी यहां पर उप-प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने आइटम नम्बर 3 को पेश किया। आप आज के आर्डर पेपर को देखिये। आइटम नौन को पढ़िये। उस में लिखा हुआ है:

"Shri Morarji R. Desai to lay on the Table a copy of the Interim Report of the Fifth Finance Commission together with the explanatory memorandum....."

आप आर्टिकल 281 को देखिये। वह यह कहता हो कि फाइनेन्स कमिशन की रिपोर्ट और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ये दोनों साथ आने चाहिए तो मंत्री महोदय यह नहीं कह सकते हैं कि मैंने तो स्टेटमेंट पहले दे दिया है अब मैं रिपोर्ट को पेश कर रहा हूं। उसी तरीके से अगर 71 (1) यह कहता हो कि विधेयक और उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आना चाहिये तो मंत्री महोदय यहां आर्डर पेपर पर यह लिख कर नहीं बता सकते हैं कि बेवकूफी की है हमारे मंत्रालय ने कि पहले ही दिन हमने उसको पेश किया है तो मान लो कि वह पेश किया गया है, इसको मानने के लिए कम से कम हम तो तैयार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ताकि सरकार और सदन दोनों को उचित मार्गदर्शन मिले। जब इस पर आपकी व्यवस्था आ जाएगी तो उसके बाद मैं अपने प्रस्ताव को पेश करूंगा और उसके बाद में इस विधेयक का विरोध करने वाला हूं।

SHRI C. M. POONACHA: There is no point of order.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : आप कौन होते हैं यह कहने वाले।

SHRI C. M. POONACHA: I have to explain the position.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): We may take it up after Lunch, because we want to discuss the point of order.

13 HRS.

The Lok Sabha adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Five minutes past Fourteen of the clock.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Poonacha.

SHRI S. M. BANERJEE: The point of order is going on.

SHRI C. M. POONACHA: There is no point at all in the point of order as I have complied with the requirements of the rules fully and there is nothing which has missed our attention.

SHRI S. M. BANERJEE: Shri George Fernandes wants to raise a point of order. Kindly listen.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is just a technical point. It does not require quite a serious thought about it because if he had raised it earlier—that he has committed, according to you, a technical error—I would ask him to refer to it along with this, but he has already laid it on the Table. So, it is not necessary.

श्री जार्ज फरनेंडाज : आप मंत्री महोदय को कहें कि वह आगे ऐसी गलती न करें। ये लोग हमेशा ऐसी गलती किया करते हैं।

MR. DEPUTY SPEAKER: That is all right. Have you got any other thing?

श्री जार्ज फरनेन्डीज : अब मैं इस विधेयक को यहां रखने के विरोध में कहना चाहता हूं। मुझे आप के सामने तीन प्रमुख बातें रखनी हैं। जब केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले थे, तब सरकार ने दो अध्यादेश जारी किये : एक तमाम सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को गैर-कानूनी तय करने वाला अध्यादेश और दूसरा रेल कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकने वाला रेलवे सम्बन्धी अध्यादेश। इस अध्यादेश के आधार पर यह नया कानून सरकार पेश कर रही है। लेकिन हिन्दुस्तान की कई हाई कोर्ट्स में इस अध्यादेश को गैर-कानूनी और संविधान के विरुद्ध सिद्ध करने के सम्बन्ध में मुकदमे चल रहे हैं, जो कई रेल कर्मचारियों अथवा उन के संगठनों ने दायर किये हैं। मेरा पहला निवेदन यह है कि जब तक उन अदालतों में वे मुकदमे चलते रहे तब तक उस अध्यादेश के सिलसिले में कोई कानून इस सदन में नहीं आ सकता है।

इस के बाद मैं आप का ध्यान संविधान के आर्टिकल 14, 19(बी०) और 21 की ओर दिलाना चाहता हूं। आर्टिकल 14 में कहा गया है :

"The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India."

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कानून इस वक्त मंत्री महोदय पेश कर रहे हैं, वह आर्टिकल 14 के बिल्कुल ही खिलाफ़ है, क्योंकि इस के द्वारा रेल कर्मचारियों को देश के अन्य नागरिकों से अलग मान लिया गया है। किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार करने, उस को अदालत में पेश करने, उस पर कानूनी कार्यवाही करने आदि के सम्बन्ध में जो कानून हैं, और एक कर्मचारी की हैसियत से किसी व्यक्ति के जो अधिकार हैं, अर्थात् वह कितने घंटे काम करे, वह कब काम बन्द करे, वह हड़ताल पर जाये या नहीं, आदि, उन कानूनों और अधिकारों की उपेक्षा कर के इस कानून में ऐसे प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं, जिन से संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन होता है।

अध्यक्ष महोदय, आप यह देखेंगे कि आर्टिकल 14 में यह बात बिलकुल साफ लिखी हुई है :

"14. The State shall not deny to any person equality before the law....".

अब इस कानून को आप देखें क्लाज़ 2, सेक्शन 10(ए०):

"If a railway servant when on duty is entrusted with any responsibility connected with the running of a train, rail-car or any other rolling-stock from one station or place to another station or place and he abandons the duty before reaching such station or place, without authority or without properly handing over such train, rail-car or rolling-stock to another authorised railway servant, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.".

अब एक रेल कर्मचारी रेलगाड़ी को दिल्ली से ले चलता है। उस की ड्यूटी मान लीजिए, कल शाम को आगरा में खत्म होने जा रही है। आगरा में गाड़ी को चलाने वाला दूसरा ड्राइवर आना चाहिए। वह ड्राइवर किसी कारणवश वहां नहीं पहुंच सका तो इस कानून के मुताबिक जो दिल्ली से रेलगाड़ी ले जायेगा, वह गाड़ी से नहीं उतर सकता है क्योंकि वहां पर उस की जगह काम पर आने वाला जो कर्मचारी है वह किसी कारण से वहां नहीं पहुंच सकता। तो इस ड्राइवर को उस गाड़ी पर ही रहना पड़ेगा। अथवा उस के काम के घंटे पूरे होने के बाद भी चूंकि उस का बड़ा अफसर उस से कहेगा कि नियम के अनुसार तुम गाड़ी को यहां नहीं रोक सकते हो, तुम को गाड़ी

आगे ले जानी होगी तो वह जब तक उस को रिलीव करने वाला न आये तब तक गाड़ी चलाता रहेगा। तो आर्टिकिल 14, जहां ईक्वलिटी बिफोर ला की बात दी है उस को ध्यान में रख कर इसके ऊपर विचार करेंगे तो यह महसूस करेंगे कि मजदूर विषयक जो कानून हिन्दुस्तान में हैं, जिसमें 8 घंटे से ज्यादा काम किसी मजदूर से नहीं लिया जा सकता है और यदि लिया जाय तो ओवर टाइम देना होगा, उस कानून को तोड़ने वाला यह कानून है और आर्टिकिल 14 के बिलकुल खिलाफ यह जाता है।

दूसरे इस के आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स में आप जायं तो इस में ऐसा आप महसूस करेंगे:

"Chapter IX of the Indian Railways Act, 1890 contains provisions for penalties for certain offences such as maliciously wrecking or attempting to wreck a train, maliciously hurting or attempting to hurt persons travelling by railway, endangering safety of persons travelling by railway by rash or negligent act or omission etc. These provisions are, however, not adequate to deal effectively with obstruction to the running of trains by abandonment thereof by railway servants, or by squatting, picketing or other means either by railway servants or by others.".

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं चाहता हूं कि आप सुन कर इस के ऊपर अपनी राय बताएं क्योंकि यह प्रस्ताव है मेरा कि यह बिल यहां पर बहस के लिये आ हो नहीं सकता है।

हिन्दुस्तान में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऐंड इंडियन पोनल कोड हैं, इन कानूनों के अन्तर्गत किसी भी नौकर ने कोई गलती की तो उस को गिफ्तार करने का, उस पर मुकदमा चलाने का, उस को सजा देने का, हर किस्म का अधिकार और हर किस्म की व्यवस्था पहले से की हुई है। कोई घटना भी हुई है तो सी० आर० पी० सी० और आई० पी० सी० मौजूद हैं, आप सजा की व्यवस्था कर सकते हैं। यह चीज रहते हुए भी जब रेलवे ऐक्ट में अमेंडमेंट कर के रेल कर्मचारी पर नय बन्धन डालने की बात कर रहे हैं तो मेरा कहना है कि आर्टिकिल 14 के यह सख्त खिलाफ है और इस बात को आप को महसूस करना चाहिए।

अब आर्टिकिल 19 देखिए : आर्टिकल 19(1)(बी०) :

"Protection of certain rights regarding freedom of speech etc. :

19. (1) All citizens shall have the right—

.....

(b) to assemble peaceably and without arms.....".

इस कानून का सेक्शन 100(बी) जो अमेंड करने जा रहे हैं वह देखिए :

"If a railway servant when on duty or otherwise or any other person obstructs or causes to be obstructed or attempts to obstruct any train, railcar or other rolling-stock upon a railway by squatting, picketing, keeping without authority any rolling-stock on the railway....".

अब आप आर्टिकिल 19(1)(बी०) देखिए :

"All citizens shall have the right—

.....

(b) to assemble peaceably and without arms;".

अध्यक्ष महोदय, आप मानेंगे, यह अधिकार तो दुनिया में हर जगह है :

"Protection of life and personal liberty".

कोई इस अधिकार को नहीं छीन सकता है। मैं यह समझ सकता हूं 144 तो इन लोगों

[श्री जार्ज फरनेन्डीज]

का कायम के लिए दिल्ली में चलता है। धारा 144 का इस्तेमाल हिन्दुस्तान में हर जनतांत्रिक आन्दोलन को खत्म करने के लिए होता है और यह तो 144 वाली सरकार है। लेकिन यह रोक लगाना संविधान के खिलाफ है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : At this stage, the scope is very limited.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : पिकेटिंग पर बन्धन लगाना आर्टिकिल 19(1) (बी०) के खिलाफ़ है।

SHRI S. M. BANERJEE : Constitutional points have been raised.

SHRI GEORGE FERNANDES : I would draw your attention to proviso to rule 72.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have permitted him because he had written to me that he wanted to oppose the Bill at the introduction stage. Therefore, I have given him an opportunity. But there is a limitation which he must bear in mind.

SHRI GEORGE FERNANDES : I am quoting rule 72. Here are certain clauses which contravene the provisions of the Constitution.

Rule 72 reads thus :

"If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker, after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may, without further debate, put the question :

Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon.".

अब, तीसरे मुद्दे पर आने से पहले मैं आर्टिकिल 21 का जिक्र कर रहा हूं। आर्टिकिल 21 क्या कहता है :

"No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.".

और अध्यक्ष महोदय, इस कानून को आप देखिए, यह रेलवे ऐक्ट जो है इसमें सेक्शन 13 देखिए :

"If a person commits any offence mentioned in sections 101, 108 etc. .....",

he may be arrested without warrant or often written authority by any Railway servant or police officer.".

यानी एक रेलवे कर्मचारी दूसरे रेलवे कर्मचारी को पकड़ कर बिठा सकता है और कह सकता है कि मैंने तुम को गिरफ्तार किया है। कोई भी व्यक्ति यानी रेल पर झाड़ू लगाने वाला एक व्यक्ति गाड़ी चलाने वाले को रोक सकता है और बोल सकता है कि आप ने गाड़ी चलाना रोका है, इसलिए मैं आप को गिरफ्तार करता हूं। गाड़ी चलाने वाला झाड़ू लगाने वाले को कह सकता है कि मैंने तुम को गिरफ्तार किया, तुम यहां पर बैठ जाओ। विदाउट वारन्ट ऐंड विदाउट एनी रिटेन एथारिटी एक रेल कर्मचारी दूसरे रेल कर्मचारी को गिरफ्तार कर सकता है। तो आप मुझे बताइए जहां आर्टिकिल 21 की बात आती है, उस में यह दिया है :

"No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.".

मेरा आप से यह नम्र निवेदन है कि यह विधेयक, जो भी इस मुल्क के कानून हैं, जो भी दुनिया के माने हुए कानून हैं, और कानूनों की बातों को छोड़ दीजिए जो नेचुरल जस्टिस की बात है, उस के भी सख्त विरोध में जाने वाला है, इसलिए यह संविधान के बिलकुल विरुद्ध है और यहां नहीं आ सकता है।

अब तीसरा मुद्दा मेरा यह है—लेजिस्लेटिव काम्पीटेंस की बात है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is the only relevant point at this stage.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : इस विधेयक के द्वारा मंत्री महोदय करना क्या चाहते हैं ? इस विधेयक के अनुसार किसी व्यक्ति पर रोक लगाना, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना और कल यहां पर बड़ी बहस चली जिस वक्त आप मौजूद थे, इंडस्ट्रिअल सिक्योरिटी फोर्स को लेकर और आर्टिकिल 246 को लेकर, मैं भी वही आर्टिकिल 246 पेश करना चाहता हूं, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट वाली बात को दोबारा दोहराना चाहता हूं। इस विधेयक के अनुसार किसी रेल कर्मचारी को पुलिस का अधिकार देने की बात होती हो, किसी भी पुलिस वाले को रेल कर्मचारी को गिरफ्तार करने देने की बात आती हो तो फिर मेरा आप से यह निवेदन है कि यह विधेयक केन्द्र सरकार यहां पर पेश नहीं कर सकती है क्योंकि पुलिस का ला ऐंड आर्डर वाला मामला, पब्लिक आर्डर वाला मामला इस में आता है और पुलिस के सम्बन्ध में, इन्क्लूडिंग रेलवे पुलिस, सेवेन्थ शिड्यूल लिस्ट 2 देखिए :

Seventh Schedule, List II, item 2 : Police, including railway and village police.

यह नहीं आ सकता है, रेल मंत्री इस विधेयक को यहां कैसे ले आ सकते हैं, जिसमें एक रेल कर्मचारी दूसरे रेल कर्मचारी को गिरफ्तार कर सकता हो, रेलवे के ऊपर स्कैवटिंग करने वाले को, पिकेटिंग करनेवाले को या अगर कोई गाड़ी देर से लाये, या गाड़ी में बत्ती न रहे, पानी न रहे, पंखा न चलता हो, ऐसी बातों को लेकर अगर कोई गाड़ी को रोके, तो उस को गिरफ्तार किया जा सकता हो।

उपाध्यक्ष महोदय, सिविल नाफर्मानी का प्रश्न आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज रेलगाड़ियों में पंखा कभी नहीं चलता, पानी नहीं मिलता, रोशनी नहीं होती है—इन की रेलगाड़ियां किस तरह से चलती हैं—यह आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक नागरिक की हैसियत से मेरा यह अधिकार है—जब मैं आपको टिकट का पूरा पैसा देता हूं, तो जो सुविधायें मुझे मिलनी चाहियें, यदि वे नहीं मिलती हैं तो गाड़ी को रोकूं। आप जब पूरा पैसा लेते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि मुझे जानवरों की तरह से रेलों में भर कर ले जायें। रेलवे एक्ट के अनुसार रेलगाड़ियों में बैठने के लिये आपको जगह देनी होगी, पानी देना होगा, बत्ती देनी होगी, पंखा देना होगा, ये सब सुविधायें हासिल करना मेरा अधिकार है, इस में आपकी तरफ से मेहरबानी की कोई बात नहीं है। अगर यह सुविधाएं नहीं देंगे तो गाड़ी को रोकने का मेरा अधिकार है और उस अधिकार को मुझ से कोई छीन नहीं सकता है। जब सिविल नाफर्मानी का सवाल आता है और इन के अनुसार अगर मैं सिविल नाफर्मानी करता हूं गाड़ी को रोकता हूं या कोई भी गुनाह करता हूं तो मेरी गिरफ्तारी का अधिकार इन के हाथ में नहीं रह सकता है, वह राज्य सरकारों के हाथ में ही रह सकता है। पुलिस के अधिकार, चाहे रेलवे पुलिस ही क्यों न हो, वह केवल राज्य सरकारों के अधिकार की ही बात हो सकती है।

इस लिये, उपाध्यक्ष महोदय यह विधेयक तीन मुद्दों के आधार पर—पहला अध्यादेश, जिसका विरोध अदालतों में हो रहा है, दूसरे तीन आर्टिकल्ज, जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है, तीसरे 246 के अन्तर्गत इस बिल को यहां पर लाने का इन को अधिकार नहीं है। इस लिये मैं इस बिल का सख्त विरोध करता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Banerjee. He should be very brief.

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN (Chamba) : You have allowed half an hour to that side. You must allow half an hour to this side also before again calling them.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Though under the rules, a full debate is permissible, that does not mean lengthy debates. Arguments already advanced should not be repeated. I will give an opportunity to Mr. Mahajan also.

SHRI S. M. BANERJEE : Kindly read the Statement of Objects and Reasons, Sir. It says :

> "Chapter IX of the Indian Railways Act, 1890 contains provisions for penalties for certain offences such as maliciously wrecking of attempting to wreck a train, maliciously hurting or attempting to hurt persons travelling by railway, endangering safety of persons...." etc.

When in this House several questions were asked repeatedly about the safety of the passengers, we were always told by the hon. Minister and his predecessor that this is a law and order question confined to the State Governments. We never get a satisfactory reply. Sir, my hon. friend has correctly raised it under article 246. Whenever any lady is murdered in a train, or somebody is robbed and we ask "What protection do you give?" the invariable answer is, "What can we do? It is a question of law and order which comes within the jurisdiction of the State Government". Only the 19th September strike brought them some wisdom and they realised that something has to be done to curb the genuine trade union activities. Of course, they are not concerned with the protection of the lives of the people: train accidents are taking place even now.

For all these reasons, I support the point raised by Shri Fernandes. This legislation is to replace an Ordinance which has been challenged in Punjab, Haryana, Kerala and other States. Then, a particular democratically elected State Government, I mean Kerala, has not cared to accept or recognise this Ordinance. So, the Centre want to take advantage of President's Rule in many States like West Bengal, Bihar, U.P. and others to legislate a provision which, according to me, is pernicious. The State Governments and the Chief Ministers should have been consulted before bringing forward such a legislation. They want to take advantage of President's Rule in many States and want to bring this legislation in this House and pass it by taking advantage of the brute majority, even though they have no competence to do so. Therefore, I would request you, Sir, to uphold the banner of parliamentary democracy in this House, which they do not do, and see to it that such a legislation is not brought before this House as long as cases or appeals are pending in High Courts and even in the Supreme Court and as long as the State Governments are not consulted. After all, the heavens are not going to fall if there is some delay. The 19th strike was over, and successfully over, and they could not check it. If they want to check anything, let them bring a lawful law.

Then, as has been pointed out by Shri Fernandes, when section 100B is passed, even peaceful picketing is going to be illegal. Picketing is a Gandhian method which has been taken over by the opposition when it has been forgotten by Congressmen. When section 36AD of the Banking Companies Act was being discussed in this House, the Deputy Prime Minister, who is supposed to be the strongest man on that side, conceded that peaceful picketing will be allowed; it is there in the proceedings of this House. Now, under this section, even that is not going to be allowed. If anybody is found to be picketing, even peacefully, he will be sentenced to two years of imprisonment, or a fine of Rs. 500 or both. Without realising the implications, without realising that such a legislation is going to be declared *ultra vires* the next day of its passing, they want to bring it before the House. Therefore, Sir, I would appeal that in all fairness these two points should be answered and, at least for the satisfaction of this House, a reference may be made to the Supreme Court for their opinion. Since we cannot rely on the opinion of Shri Sheo Narain, at least in this case, it should be referred either to the Supreme Court or the Attorney-General.

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN : My submission is that this Bill is trying to do only very little. Suppose a train is going from Delhi to Calcutta. On the way, let us say near Lucknow, the driver gets out of the train in a small wayside station and walks away. Then, according to this Bill, the driver will be penalised. Now, what are our learned friends saying? They are saying that the act of the driver is not penal, he has a right to get out of the train and thereby punish the one thousand passengers travelling in that train, starving them of food and water. This is the constitutional point they are trying to raise by referring to articles 14 19, and 21. Now, what does article 19 say? 19(1)(a) refers to freedom of speech, (b) to peaceful assembly without arms and (c) to formation of associations. These are the clauses read out by our learned friends. Kindly read the further clauses also to see whether they give power to the government to bring forward such a legislation.

Clause (3) says :—

"Nothing in sub-clause (b) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of public order, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause."

Clause (4) says :—

"Nothing in sub-clause (c) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of public order or morality reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause."

Now the question is : Is it in the public interest not to permit a driver to walk off the train and leave 1,000 passengers stranded on the way? Is it a reasonable restriction or not?

My submission is that this Bill is only giving the power to Government to punish those drivers and railway employees who stop the trains on roadside stations and injure the public interest, the interest of the majority of Indians; this is a Bill which seeks to prevent goondaism in the public interest. Therefore, I submit that it is constitutionally valid.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : Mr. Deputy-Speaker, only two points are relevant. The first point is that when the Ordinance has been challenged in the Supreme Court or in the different High Courts, Parliament is competent to amend the Indian Railways Act. This amendment of the Railways Act deals with one single factor.

Clause 5 says :—

"The Indian Railways (Amendment) Ordinance, 1968, is hereby repealed."

The second point is that by amending the Railways Act as it exists today, the amendment infringes upon the fundamental rights.

SHRI GEORGE FERNANDES : Legislative competence.

SHRI R. D. BHANDARE : Legislative competency is covered by the first point. There is no validity in that.

SHRI GEORGE FERNANDES : Article 246.

SHRI R. D. BHANDARE : I quite follow that.

The third point that they have mentioned is whether the powers to deal with offenders could be given. I think, this point has been dealt with here for a long time. Yesterday also the same point was raised. As I said yesterday, the Criminal Procedure Code even in the ordinary course gives power to ordinary citizens to apprehend and hand over to the police a person who commits an offence. The same power is sought to be given here.

SHRI C. M. POONACHA : The points raised have been ably met by my hon. friends, Shri Mahajan and Shri Bhandare. There is not much for me to add to that. But what I would like to add is that the question has been asked whether we have any power to authorise a railway employee to arrest a person. My hon. friend himself quoted the

relevant section as it now exists in the Act. The Railway Act does contain that. Section 131 gives that power. What is attempted to be done by this piece of legislation is that additional sections are going to be incorporated in the Act to the provisions which already exist. It is not as if I am trying to introduce a completely new measure which is unknown to the world and which is against the ethics of jurisprudence. It is not so. The power is there and what is sought to be done is to enumerate these amendments which are now being sought to be made by this Amendment Bill in the relevant section which already exists in the Act. This particular authority already exists in the Act and it has not so far, I am sure, been misused. There has been no such instance.

As for the right to picket and offer satyagraha, a point has been made as related to article 19 of the Constitution. It may be all right in a public place. But here it is the railway track, railway property, and the safety and convenience of passengers, and public order demands that the efficient functioning and normal running of railways should be ensured. For such a purpose, here is a Bill which is being brought forward.

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappali) : On a point of clarification.

MR. DEPUTY-SPEAKER : No. You were not here.

SHRI S. M. BANERJEE : On a point of clarification. He said about picketing in a public place. Is it his opinion that picketing in a public place is all right? That contradicts Shri Morarjibhai.

SHRI NAMBIAR : The law of the land is already there.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You were not here. You have not followed the arguments. I know you have many things to say. You are too late.

SHRI NAMBIAR : The law of the land is already there. Why should the Indian Railways Act be amended for this purpose?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Order, order. That is all. (*Interruption*)

Some of the points raised by Shri George Fernandes and Shri S. M. Banerjee have been replied to by Shri Mahajan and Shri Bhandare. Further clarification about picketing, the existing penalty section and other things has been given by the Railway Minister.

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : On the point that it is the States that have got power over police including Railway Police, what is the answer he has given? I have not heard it. He has not replied to that.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Yesterday, the same question was raised whether any legislation that is brought before the House contravenes any article of the Constitution or any provision of the Constitution or infringes certain rights conferred under the Constitution to the States, it is a matter for the highest judiciary to take into consideration.

SHRI TENNETI VISWANATHAM: Supposing a Bill is brought here on land revenue, will it be admitted?

MR. DEPUTY-SPEAKER : It would be *per se* out of order. I do not think that could come before the House.

SHRI TENNETI VISWANATHAM: This is police including railway police which is a State subject. It is so clear.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I do not think this legislation is of that nature.

SHRI TENNETI VISWANATHAM: Then Government can pass any legislation..... (*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : In the last twelve years, I have not come across any legislation from this side which obviously belongs to the States' sphere.

Now, all the objections raised on the ground of competence are overruled. So, I put the question to the vote of the House.

The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Railways Act, 1890."

The Lok Sabha divided :

Division No. 4] AYES **14.44 Hrs.**

Ahirwar, Shri Nathu Ram
Amat, Shri D.
Arumugam, Shri R. S.
Barua, Shri Bedabrata
Barua, Shri R.
Barupal, Shri P. L.
Baswant, Shri
Bhandare, Shri R. D.
Bhattacharyya, Shri C. K.
Buta Singh, Shri
Chanda, Shrimati Jyotsna
Dass, Shri C.
Deb, Shri D. N.
Desai, Shri Morarji
Deshmukh, Shri B. D.
Deshmukh, Shri K. G.
Dhillon, Shri G. S.
Girja Kumari, Shrimati
Gowd, Shri Gadilingana
Gudadinni, Shri B. K.
Gupta, Shri Lakhan Lal
Jadhav, Shri V. N.
Joshi, Shri Jagannath Rao
Kamble, Shri
Kamala Kumari, Kumari
Katham, Shri B. N.
Kureel, Shri B. N.
Lakshmikanthamma, Shrimati
Laskar, Shri N. R.
Lobo Prabhu, Shri
Lutfal Haque, Shri
Mahajan, Shri Vikram Chand
Maihshi, Dr. Sarojini
Majhi, Shri M.
Mandal, Dr. P.
Mandal, Shri Yamuna Prasad
Master, Shri Bhola Nath
Mirza, Shri Bakar Ali
Mishra, Shri Bibhuti
Mondal, Shri J. K.
Mulla, Shri A. N.
Naik, Shri G. C.
Nayar, Dr. Sushila
Pandey, Shri K. N.
Panigrahi, Shri Chintamani
Paokai Haokip, Shri
Parmar, Shri D. R.
Parthasarathy, Shri
Patel, Shri N. N.
Poonacha, Shri C. M.
Pradhani, Shri K.
Pramanik, Shri J. N.
Prasad, Shri Y. A.
Radhabai, Shrimati B.
Raju, Shri D. B.
Ram Subhag Singh, Dr.
Rane, Shri
Rao, Shri J. Ramapathi
Rao, Shri Thirumala
Raut, Shri Bhola
Saha, Dr. S. K.
Saigal, Shri A. S.
Sanjit Rupji, Shri
Sen, Shri Dwaipayan
Sen, Shri P. G.
Shah, Shri Manabendra
Sharma, Shri D. C.
Sharma, Shri Naval Kishore
Shashi Bhushan, Shri
Shastri, Shri B. N.

Sheo Narain, Shri
Sher Singh, Shri
Shinkre, Shri
Shiv Chandika prasad, Shri
Shukla, Shri Vidya Charan
Siddayya, Shri
Siddheswar Prasad, Shri
Sinha, Shrimati Tarkeshwari
Snatak, Shri Nar Deo
Solanki, Shri S. M.
Supakar, Shri Sradhakar
Suryanarayana, Shri K.
Swaran Singh, Shri
Tapuriah, Shri S. K.
Uikey, Shri M. G.
Ulaka, Shri Ramachandra

NOES

Banerjee, Shri S. M.
Basu, Shri Jyotirmoy
Bharati, Shri Maharaj Singh
Chakrapani, Shri C. K.
Dar, Shri Abdul Ghani
Fernandes, Shri George
Ganpat Sahai, Shri
Gopalan, Shri P.
Goyal, Shri Shri Chand
Gupta, Shri Indrajit
Haldar, Shri K.
Jha, Shri Shiva Chandra
Jharkhande Rai, Shri
Kapoor, Shri Lakhan Lal
Maiti, Shri S. N.
Meghachandra, Shri M.
Menon, Shri Vishwanatha
Mukerjee, Shri H. N.
Nair, Shri N. Sreekantan
Nair, Shri Vasudevan
Nambiar, Shri
Nihal Singh, Shri
Patil, Shri N. R.
Ramamurti, Shri P.
Ramji Ram, Shri
Satya Narain Singh, Shri
Sen, Shri Deven
Sen, Dr. Ranen
Shah, Shri T. P.
Suraj Bhan, Shri
Viswambharan, Shri P.
Viswanatham, Shri Tenneti

MR. DEPUTY-SPEAKER: The result* of the Division is: Ayes—86; Noes—32.

The motion was adopted.

SHRI C. M. POONACHA : I introduce the Bill.

---

*The following Members also recorded their votes :

AYES : Shri S. D. Patil, Shri Ganpat Sahai and Shri Kushok Bakula.

NOES : Shri Om Prakash Tyagi and Shri S. S. Kolthari.